



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

26 वैशाख 1939 (श0)  
(सं0 पटना 391) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

---

सं0 08/आरोप-01-184/2014,सां0प्र0-224

सामान्य प्रशासन विभाग

---

संकल्प

10 जनवरी 2017

श्री प्रमोद कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-825/11, के विरुद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास के पद पर पदस्थापन के दौरान धान अधिप्राप्ति कार्य के नोडल पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण में अभिरुचि नहीं लेने के आरोपों से आच्छादित आरोप, प्रपत्र 'क' खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4614, दिनांक 22.07.2013 द्वारा प्राप्त हुआ। जिसमें उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा भी निहित थी। विभागीय पत्रांक-15846, दिनांक 19.11.2014 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में उन्होंने साक्ष्य की पठनीय प्रतियाँ माँगी जिसे संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त कर उन्हें उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। आरोप की गम्भीरता को देखते हुए सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7445, दिनांक 20.05.2015 द्वारा श्री कुमार को निलंबित कर दिया गया। उक्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7446, दिनांक 20.05.2015 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक-88 (अनु०) दिनांक 23.02.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों में से आरोप सं०-05 को आंशिक रूप से प्रमाणित बताया गया। विभागीय पत्रांक-3388, दिनांक 09.03.2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से बचाव बयान/लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री कुमार ने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 16.03.2016) समर्पित किया जिसमें उन्होंने प्रमाणित आरोप पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते

हुए आरोप मुक्त करने एवं पदस्थापन करने का अनुरोध किया। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7012, दिनांक 17.05.2016 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया। इस क्रम में आरोप एवं जाँच प्रतिवेदन की गहन/सूक्ष्म समीक्षा में आरोप सं०-1,3 एवं 9 पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। जिसके आलोक में आरोप सं०-1,3 एवं 9 पर अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति के विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक-7023, दिनांक 17.05.2016 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में उन्होंने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 06.07.2016) समर्पित किया।

3. तत्पश्चात् आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन की समेकित समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि वर्ष 2011-12 में श्री कुमार के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान चावल की एक बड़ी मात्रा का गबन हुआ, जिसमें मूल रूप से राज्य खाद्य निगम, रोहतास के जिला प्रबंधक एवं सहायक गोदाम प्रबंधक की भूमिका घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता भी कारण होगा। इसके बावजूद यदि नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार समुचित ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समय-समय पर समीक्षा/अनुश्रवण करते तो राजस्व की इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। इस परिप्रेक्ष्य में उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरुद्ध तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-12690, दिनांक 19.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में दी गयी "सहमति" बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2753, दिनांक 21.12.2016 द्वारा प्राप्त हुई।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री प्रमोद कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-825/11 के विरुद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

(क) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 20.05.2015 से दिनांक 17.05.2016) पर निर्णय हेतु अलग से कार्रवाई की जायेगी।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 391-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>